Concession in interest on finance to industries

3182. SHRI P. UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether large and medium industries, including export units, have requested for concession in interest on finances made available to them;

(b) whether the small scale sector has also made a similar demand; and

(c) what is the reaction of Government to these suggestions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Government is considering these demands.

CBI monitorng Maruti Udyog Limited

3183. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem which appeared in the Statesman, Delhi of 28th June, 1992 under the caption "Maruti's land for land's sake";

(b) whether it is a fact that CBI has been monitoring all MUL deals for a long time; and

(c) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) (a) to (c) Yes, Sir. CBI started discreet verifications about certain irruSgularities allegedly committed by certain officials of Maruti Udog Limited (MUL) in this deal. At the request of CBI, MUL's file on the subject has since been made available to CBI. It is not correct to say that CBI has been monitoring all MUL deals for a long time.

ग्रामीण और लघु स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन

3184. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने उद्यमियों के लाभान्वित होने की संभावना है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) :(क)ग्राम्य और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । किन्तु, केन्द्र सरकार सस्ता और सुलभता से उपलब्ध वित्त का प्रावधान, प्रौद्योगिकी का अंतरण, दुर्लभ और महत्वपूर्ण कच्चे माल के प्रावधान में सहायता तथा अखिल भारतीय स्तर पर संस्थान संबंधी बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने जैसे उपायों से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है । लघु उद्यमियों को सेवायें और सहायता प्रदान करने तथा उनको ग्रामीण व लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता देने हेतु देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये हैं । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का सारे देश में लघु उद्योगों और ग्राम उद्योगों का विकास करने पर अधिकाधिक जोर देने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु तथा खादी ग्रामोद्योग के जरिये लगभग 41.5 लाख